इमरजेंसी और मोदी सरकार

मनोज कुमार झा

देश में लोकतंत्र का जो मौजूदा ढांचा है, बहुत से लोग़ों का मानना है कि उसमें बुनियादी खामी है। इस ढांचे में जनता की भूमिका महज एक वोटर की है। इसके अलावा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसकी कोई खास भूमिका नहीं है। जनता हिंदू-मुसलमान, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक, अगड़ा-पिछड़ा-दलित जैसे खांचे में बंटी है और राजनीतिक दल जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर उसे विभाजित कर वोटबैंक के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में, जनता के मूल मुद्दे कभी भी उभर कर सामने नहीं आ पाते। राजनीतिक दल और नेता इतने शातिर हैं कि विकास की बातें करते हुए उसे दूसरे मुद्दों में उलझा देते हैं और अपना हित साधते हैं। खास बात यह है कि वर्तमान मोदी सरकार ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से ऐसा करना शुरू कर दिया है। विकास के नाम पर आई मोदी सरकार एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विकास का एक भी काम नहीं कर सकी है, लेकिन ऐसे कोई तमाशे जरूर आयोजित किए हैं, जिससे जनता में असंतोष व्याप्त होता जा रहा है।

चार दशक पहले देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे देश के इतिहास में काला अध्याय बताया है। क्या विडंबना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 'अनुशासन पर्व' घोषित किया था। और क्या यह भी संयोग ही है कि चंद दिन हुए भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि देश में इमरजेंसी की स्थितियों की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है, यद्यपि अब ऐसा हो पाना मुश्किल है। आडवाणी के ऐसा कहते ही कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इमरजेंसी के प्रयोग उनकी ही सरकार पर हो रहे हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा देश में इमरजेंसी जैसी पस्थितियां बनती जा रही हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आडवाणी ने ऐसा बयान देकर अपनी कुंठा को जाहिर किया है, क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें और उनके खेमे के नेताओं को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। सरकार अथवा पार्टी में अब उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। सवाल है, क्या देश में फ़िर से इमरजेंसी लागू हो सकती है? इसका जवाब तक मिल सकता है जब हम पता करें कि इंदिरा गांधी ने किन परिस्थितियों में देश में इमरजेंसी थोपी थी और नागरिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन कर दिया था। इंदिरा गांधी ने चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध ठहरा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी थी। यानी सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया था। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के सामने इस्तीफ़ा देने के सिवा और कोई चारा नहीं था, पर अपने चंद विश्वस्त लोगों की सलाह पर उन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपने का ही निर्णय लिया। इसका परिणाम क्या हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है। तमाम विरोधी नेताओं को रातोंरात जेल में ठूंस देने और बड़े पैमाने पर दमनचक्र चलाने के बावजूद आखिरकार उन्हें चुनावों का सामना करना ही पड़ा और जनता ने उन्हें नकार दिया। देश पर इमरजेंसी थोपने का एक बड़ा करण हर मोर्चे पर इंदिरा सरकार की विफलता थी और जिसके परिणामस्वरूप गुजरात से शुरू हुआ छात्र आंदोलन बिहार के साथ पूरे देश में फैलता जा रहा था। जयप्रकाश नारायण ने अवज्ञा आन्दोलन की अपील कर दी। इससे बचने का एक ही तरीका इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों की समझ में आया कि नागरिक अधिकारों का अपहरण कर लिया जाए और इमरजेंसी लगा दी जाए। विरोध की हर आवाज़ को कुचल दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकीं। ये अलग बात है कि मजबूत विकल्प के अभाव में फ़िर से वे सत्ता में आ गईं।

देश में लोकतंत्र का जो मौजूदा ढांचा है, बहुत से लोग़ों का मानना है कि उसमें बुनियादी खामी है। इस ढांचे में जनता की भूमिका महज एक वोटर की है। इसके अलावा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसकी कोई खास भूमिका नहीं है। जनता हिंदू-मुसलमान, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक, अगड़ा-पिछड़ा-दलित जैसे खांचे में बंटी है और राजनीतिक दल जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर उसे विभाजित कर वोटबैंक के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में, जनता के मूल मुद्दे कभी भी उभर कर सामने नहीं आ पाते। राजनीतिक दल और नेता इतने शातिर हैं कि विकास की बातें करते हुए उसे दूसरे मुद्दों में उलझा देते हैं और अपना हित साधते हैं। खास बात यह है कि वर्तमान मोदी सरकार ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से ऐसा करना शुरू कर दिया है। विकास के नाम पर आई मोदी सरकार एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विकास का एक भी काम नहीं कर सकी है, लेकिन ऐसे कोई तमाशे जरूर आयोजित किए हैं, जिससे जनता में असंतोष व्याप्त होता जा रहा है। मोदी के सफ़ाई अभियान, योग और दूसरे कदमों ने लोगों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि यह सरकार आखिर कर क्या रही है। मोदी के 'मेक इन इंडिया' और इस जैसी दूसरी योजनाएं पूरी तरह फ़र्जीवाड़ा साबित हुई हैं। जहां तक दूसरे देशों से संबंधों का सवाल है, इस मोर्चे पर भी सरकार अब तक पूरी तरह फ़ेल रही है। पाकिस्तान के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण ही हुए हैं। चीन और रूस जैसे देशों में भी अच्छे और विश्वसनीय संबंध नहीं बन सके। महंगाई लगातार बढती जा रही है और आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। प्रधानमंत्री मोदी देश में भाषण दे या विदेश में, ऐसा लगता है कि वह चुनाव प्रचार के मोड में ही हैं। सरकार का पूरा ध्यान राज्य में होने वाले चुनावों पर है। इस बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और संघ परिवार के अन्य संगठन अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ लगातार विषवमन कर रहे हैं। साधु-संत और साध्वियों का एक ही काम रह गया है अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाना। किसी भी बात पर ये मुसलमानों या विरोध करने वालों को सीधा पाकिस्तान चले जाने को कहते हैं। यह सिलसिला चुनाव पूर्व से अब तक चला आ रहा है। मोदी सरकार बनने के बाद से संघ लगातार अपना एजेंडा लागू करने को उद्धत दिखाई पड़ रहा है। शिक्षण संस्थानों को लेकर इतिहास-सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों एवं विभिन्न अकादमियों में संघ के लोग बैठाए जा रहे हैं, जिसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है, पर सरकार अपना काम करती जा रही है। इधर, अर्थवयवस्था की हालत खस्ता है। 'मेक इन इंडिया' फ्लॉप हो गया। हालत ये है कि विदेशों से कर्ज तक मिल पाना मुश्किल है। इधर, तरह-तरह के शो पर मोदी सरकार जो धन लुटा रही है, उसकी पूर्ति वह कीमतें बढा कर और टैक्स में बढोत्तरी कर के कर रही है। इससे जनता में धीरे-धीरे असंतोष गहराता ही जाएगा। आने वाले चुनावों में मोदी और संघ का एक ही एजेंडा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसे देखते हुए संघ परिवार द्वारा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की तैयारी चल रही है। जाति आधारित समीकरणों के साधने पर भी जोर दिया जा रहा है, पर ऐसा लगता है कि मोदी जी की दाल नहीं गल पाएगी। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। मोदी सरकार और संघ के भविष्य के लिये ये चुनाव बहुत ही महत्तवपूर्ण हैं। संघ परिवार के संगठन इसे देखते हुए ही राममंदिर निर्माण का मुद्दा फ़िर से उठा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए संतों-महंतों ने यह घोषणा की है कि जब तक वहां भाजपा की सरकार नहीं बनती, राममंदिर के मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा, यानी तब तक मोदी जी को राहत दी जाएगी। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे लड़ा जाएगा। इस ध्रुवीकरण से लोकसभा चुनाव में भाजपा को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसलिए भाजपा और मोदी का एक ही एजेंडा है और वह है साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण।

नरेन्द्र मोदी संघ की विचारधारा के अनुरूप ही सर्वसत्तावादी हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रियों का कोई वजूद नहीं है। वो महज रबर की मुहर मात्र हैं। सारी शक्ति मोदी जी के पास है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वायत्तता ही जनता के अधिकारों की पहचान होती है। पर संघ और मोदी के नेतृत्व में भाजपा की विचारधारा स्वायत्तता विरोधी है। फ़िर क्या जब देर-सबेर जन असंतोष फूट पड़ेगा, तो मोदी देश पर इमरजेंसी थोप सकते हैं? बहुत से लोग़ों को ऐसी आशंका है। लेकिन यह नहीं भूलना होगा कि इमरजेंसी थोपने पर जब इंदिरा गांधी को जनता ने उनकी हैसियत बता दी थी, तो ये मोदी और संघ क्या चीज़ हैं? जिस राह पर ये सरकार चल रही है, उसे देखते हुए आज नहीं तो कल जन असंतोष भड़केगा ही। आज मोदी इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला अध्याय बता रहे हैं, पर इस बात को भूल रहे हैं कि स्वयं उनकी और संघ की विचारधारा क्या है, जिसके वे सिपहसालार हैं। मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार और काला धन को मुद्दा बनाया था, पर कौन नहीं जानता कि मोदी सरकार में एक से बढ कर एक भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। गडकरी तो इसका ऐ उदाहरण मात्र हैं। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक फंसी हुई हैं और सरकार को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है, वहीं भाजपा में मोदी के विरोध में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। मोदी सरकार की असलियत आम जनता को बहुत जल्दी समझ में आने लगी है। वैसे भी यह सरकार विकल्पहीनता की स्थिति के कारण अस्तित्व में आई, पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें इसका दोबारा सत्ता में आ पाना मुश्किल होगा। जहां तक इमरजेंसी को लेकर बयानबाज़ी का सवाल है, तो यह एक सर्वसत्तावादी सरकार के लिये हास्यास्पद ही लगता है। मोदी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जल्दी ही उसे व्यापार जन असंतोष का सामना करना पड़ेगा, फ़िर वह उससे कैसे निपटेगी?

तुर्की-ब-तुर्की / जंग-ए नजीब है कितनी अजीब

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपनी ही सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के खिलाफ़ एक जंग छेड़ रखी है। केजरीवाल सरकार के पास एक ज़रा सा एंटी करप्शन ब्यूरो का रहना भी हजम नहीं हो रहा। लिहाज़ा केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के इशारे पर उपराज्यपाल महोदय ने हर हाल में इस ब्यूरो को पटरी से उतारने की ठानी हुई है। अन्तिम हथियार के रूप में एक इशारे पर नाचने वाले पुलिस अफ़सर को जंग ने ब्यूरो का प्रमुख बना कर बैठा दिया है।

हमारा कहना है-

- जंग साहब हमें आपका सारा इतिहास अच्छी तरह पता है। रिटायर हो कर पुरस्कारस्वरूप अम्बानी ने आपको अपनी नौकरी में रखा क्योंकि सेवाकाल के दौरान आपने उसकी कम्पनियों के हितों की खासी अच्छी देख-भाल की थी। अम्बानी ने ही आपकी सेवाओं से खुश होकर यू पी ए सरकार में पहले आपको जामिया मिलिया वि.वि. का कुलपति और फ़िर दिल्ली का उपराज्यपाल लगवाया। अम्बानी की भारतीय राजतंत्र पर इतनी पकड़ है कि कांग्रेसी सरकार जाने के बाद भी भाजपा की मोदी सरकार ने आपको इसी पद पर कायम रखा। जाहिर है आपमें थाली के बैगन वाली सिफ़्त भी होगी ही।
- किसी से छिपा नहीं है कि अपने आकाओं की कृपा पाने के लिये जंग साहब आप कितना नीचे तक गिर सकते हैं। मोदी और राजनाथ सिंह के इशारे पर नाचने वाली एक कठपुतली जैसी स्थिति हैआप की। मानना पड़ेगा कि आप अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। इशारा मिलते ही केजरीवाल सरकार के किसी भी आदेश को पलटने में आप एक मिनट भी नहीं लगाते।
- खासतौर पर दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो का हाल तो आपने पूरी तरह हास्यास्पद बना दिया है। कच्चा-पक्का जैसा भी बन पड़ रहा था यह ब्यूरो, केजरीवाल सरकार के आने के बाद, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में उतर पड़ा था छोटे-मोटे ही सही इसने दर्जनों मामले पकड़े और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की मुहिम को रफ़्तार देने का काम किया। पर इतना भी मोदी और राजनाथ को बर्दाश्त न हुआ। बस उनके इशारों पर आप पालतू कुत्ते की तरह भोंकने लगे और अपनी कारगुजारियों से ब्यूरो को ही ठप कर दिया।
- जंग साहब शायद आप भूल गये कि इस देश में न्यायपालिका नाम की भी एक संस्था है। दिल्ली सरकार ने ठीक ही मामले को हाई कोर्ट ले जाने का निर्णय लिया है। वहां से आपको जूते ही पड़ने हैं। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस की इस दलील को कचड़े के डिब्बे में डाल चुकी है कि दिल्ली सरकार के एसीबी को केन्द्रीय गृहमन्त्रालय के नीचे काम करने वाली दिल्ली पुलिस के किसी सदस्य को पकड़ने की शक्तियां नहीं हैं। यह भी तय है कि अन्ततः आप जैसे 'वफ़ादार' नौकरशाह को कूड़े के ढेर में ही फ़ेंका जायेगा।